राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 17003/2021

विष्णु सिंह रावत पुत्र श्री विरद सिंह, उम्र लगभग 24 वर्ष, जाति रावत, निवासी वी.पी.ओ. बारटू भीम, जिला राजसमंद (राजस्थान)।

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, मार्फ़त सचिव, गृह विभाग, सचिवालय, जयपुर (राजस्थान)।
2. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, जयपुर (राजस्थान)।
3. महानिरीक्षक पुलिस (भर्ती), पुलिस मुख्यालय, जयपुर (राजस्थान)।
4. पुलिस अधीक्षक, जिला राजसमंद (राजस्थान)।

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री एम.एस. गोदारा।
श्री सुधीर सरूपरिया।

प्रतिवादी की ओर से : श्री राजपाल सिंह भाटी के लिए
श्री ऋतु राज सिंह।

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

13/02/2025

1. यहाँ याचिकाकर्ता, अन्य बातों के साथ-साथ, दिनांक 23.11.2021 (अनुलग्नक-5) के उस आदेश को रद्द करने की मांग करता है, जिसके माध्यम से उसे नियुक्ति के लिए अयोग्य माना गया था, और दिनांक 25.05.2018 के विज्ञापन के अनुसार कांस्टेबल के पद पर अपनी नियुक्ति का अनुरोध करता है।

2. पहले संक्षेप में तथ्य। याचिकाकर्ता के विरुद्ध एक आपराधिक मामला 16.01.2018 को उसके पक्ष में हल हो गया था। इसके बाद, प्रतिवादियों ने 25.05.2018 को एक अधिसूचना/विज्ञापन जारी किया, जिसमें कांस्टेबल (सामान्य) के पद सहित विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसके लिए

याचिकाकर्ता ने, पूरी तरह से पात्र होने के कारण, 06.06.2018 को आवेदन किया था। परीक्षा के सभी चरणों को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद, उसका चयन किया गया और उसे नियुक्ति के लिए राजसमंद जिले को सौंपा गया। इस बीच, 02.03.2020 को एक अधिसूचना जारी की गई जिसमें अयोग्यता मानदंडों को रेखांकित किया गया, जिसमें समझौते (राजीनामा) के माध्यम से हल किए गए मामले शामिल थे। नियुक्ति प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, याचिकाकर्ता को दिनांक 15.06.2021 के एक पत्र के माध्यम से भीम के एस.एच.ओ. के माध्यम से चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन से गुजरने के लिए कहा गया था, जिसे उसने निर्धारित समय के भीतर विधिवत पूरा किया। हालांकि, सभी आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के बावजूद, उसे दिनांक 23.11.2021 का एक आदेश/पत्र प्राप्त हुआ, जिस पर यहाँ आपत्ति जताई गई है, जिसमें उसे समझौते के माध्यम से एक आपराधिक मामले के पूर्व समाधान के कारण नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित किया गया, भले ही मामला वर्षों पहले उसके पक्ष में निपटाया जा चुका था। व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर की है।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और मामले की पत्रावली का अवलोकन किया है।

4. जहाँ तक प्रतिवादियों के तथ्यात्मक दावे का संबंध है, जवाब के परिच्छेद 2 और 6 में निम्नलिखित स्पष्ट रुख लिया गया है, जिन्हें यहाँ नीचे उद्धृत किया गया है: -

> *"2.* रिट याचिका के परिच्छेद संख्या *2* में निहित अभिकथन उस हद तक स्वीकार किए जाते हैं जहाँ तक वे दिनांक *25.05.2018* के विज्ञापन, अनुलग्नक *1* के अनुरूप हैं। हालाँकि, इसके बाद जिला राजसमंद में पदों की संख्या के संबंध में एक छोटा संशोधन भी जारी किया गया और कुल *139* पदों का विज्ञापन किया गया। याचिकाकर्ता ने उक्त विज्ञापन के अनुसरण में ऑनलाइन आवेदन किया, लेकिन बहुत अजीब तरह से, इस बात का पूरा ज्ञान होने के बावजूद कि उसके विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज है, उसने आवेदन पत्र में उसी का उल्लेख नहीं किया, जबकि 'नहीं' शब्द का उल्लेख किया, जो याचिकाकर्ता के आवेदन से स्पष्ट है। इस प्रकार याचिकाकर्ता द्वारा जानबूझकर और इरादतन छिपाने/दबाने का एक कार्य किया गया, जो स्वयं ही उसे इस माननीय न्यायालय से कोई राहत पाने का हकदार नहीं बनाता है।
>
> *xxxxxxxxxxxx*
>
> *6.* हालाँकि रिट याचिका के परिच्छेदसंख्या *6* में निहित अभिकथनों का एक उपयुक्त जवाब यहाँ उपरोक्त पैरा संख्या *3* और *4* में पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, लेकिन दोहराव के जोखिम पर यह फिर से दोहराया

जाता है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ता को धारा *143, 324/149* के तहत पर्याप्त साक्ष्य के अभाव के कारण संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, जिसे कानूनी तौर पर किसी भी तरह से 'सम्मानजनक दोषमुक्ति' नहीं कहा जा सकता है और आगे धारा *341, 323/149* भा.द.सं. के तहत अपराध के लिए पक्षों के बीच दर्ज समझौते के आलोक में उसे बरी कर दिया, जिसे भी 'सम्मानजनक दोषमुक्ति' नहीं कहा जा सकता है। हालाँकि, विभागीय समिति ने याचिकाकर्ता के मामले की सावधानीपूर्वक जाँच करने के बाद और दिनांक *02.03.2020* की अधिसूचना के बिंदु संख्या *02* पर भरोसा करते हुए याचिकाकर्ता को कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य नहीं पाया, जो पूरी तरह से न्यायसंगत, कानूनी और कानून के अनुरूप है और इस माननीय न्यायालय द्वारा संधारण योग्य है।"

5. आपराधिक मामले के अप्रकटीकरण के कथित छिपाव ने प्रतिवादियों के दिमाग में याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी को खारिज करते समय शायद असर डाला। हालाँकि, जिस बात से वे अनभिज्ञ थे, वह यह तथ्य था कि आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि, यानी 14.06.2018 तक, याचिकाकर्ता को विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही दोषमुक्त कर दिया गया था और वह बरी हो चुका था, हालाँकि, निस्संदेह, एक समझौते के कारण।

6. एक नागरिक, जिसे आपराधिक मुकदमे से बरी कर दिया जाता है, उसे खुद को देश के एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में मानने का पूरा अधिकार है और उसे खुद को किसी भी तरह से विचाराधीन कैदी या संदिग्ध या दोषी के रूप में नहीं मानना है और इसलिए, उसने आवेदन भरते समय विकल्प 'नहीं' का सही चयन किया।

7. वैसे भी, याचिकाकर्ता को कानून की एक सक्षम अदालत द्वारा सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। यह तुच्छ लग सकता है, लेकिन निर्दोषता के अनुमान के सिद्धांत पर, दोषमुक्ति याचिकाकर्ता की स्थिति को कानून का पालन करने वाले नागरिक के रूप में बहाल करती है। प्रतिवादियों का रुख कि दोषमुक्ति "सम्मानजनक" नहीं थी, केवल काल्पनिक है। दोषमुक्ति तब तक वैध रहती है जब तक कि अपील में इसे अपास्त नहीं किया जाता। राज्य द्वारा दोषमुक्ति के विरुद्ध ऐसी कोई अपील दायर नहीं की गई थी। याचिकाकर्ता को केवल एक प्राथमिकी/मुकदमे के कारण नियुक्ति से वंचित करना, जिसमें उसे सक्षम न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया है, प्रतिवादी/संभावित नियोक्ताओं द्वारा उसे दंडित करने के समान है।

7.2. विचारण के बाद बरी हुए व्यक्ति को अतीत में आपराधिक मुकदमे का हिस्सा होने के लिए कलंकित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, बरी हुए अभियुक्त को रोजगार का अवसर देने से इनकार करना, ऐसे व्यक्तियों को समाज में पुन: एकीकृत करने के सिद्धांत के विरुद्ध है। ऐसा होने के कारण, मैं कोई कारण नहीं देखता कि प्रतिवादीकिस आधार पर यह दलील दे रहे हैं कि याचिकाकर्ता दोषमुक्ति के किसी भी लाभ का हकदार नहीं है।

8. इस संदर्भ में, मुझे राजेंद्र मीणा बनाम राजस्थान राज्य और अन्य: एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 15957/2021 नामक मामले में एक निर्णय देने का अवसर मिला है। उसके प्रासंगिक भाग परिच्छेद 12 से 20 हैं जिन्हें संक्षेप के लिए यहाँ पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है।

9. मेरे द्वारा शंकर लाल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 756/2022 में भी यही मत लिया गया था, जिसका निर्णय 18.11.2024 को किया गया था।

10. परिणामस्वरूप, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आज की तारीख में पद की उपलब्धता के अधीन, उसकी पात्रता और योग्यता का निर्धारण करके, विचाराधीन पद पर याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर विचार करें।

11. कहने की आवश्यकता नहीं है कि यदि याचिकाकर्ता को योग्य पाया जाता है, तो ही उसे उसके प्रदर्शन का लाभ दिया जा सकता है। इस घटना में कि वर्तमान में कोई रिक्ति उपलब्ध नहीं है, अगली रिक्ति उत्पन्न होते ही उसे पद के लिए विचार किया जाएगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता को सभी सांकेतिक लाभ, जिसमें वरिष्ठता भी शामिल है, उसी तारीख से प्रदान किए जाएंगे जिससे उसके समकक्षों को उस चयन प्रक्रिया के अनुसरण में नियुक्त किया गया था जिसमें याचिकाकर्ता ने भी उनके साथ प्रतिस्पर्धा की थी। हालाँकि, जिस अवधि के लिए वह सेवा से बाहर रहा, उस अवधि के लिए वह 'कोई काम नहीं, कोई वेतन नहीं' के सिद्धांत पर किसी भी वित्तीय लाभ का हकदार नहीं होगा।

13. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निपटारा किए जाते हैं।

(अरुण मोंगा), न्यायमूर्ति

118-धनंजयएस/आरमाथुर/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ / नहीं

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

एडवोकेट विष्णु जांगिड़